



शुभ लाभ

खबरें जो सोच बदल दे
हिन्दी दैनिक समाचार पत्र



Postal Regd.No. HQ/SD/523/2023-25 | गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025 | हैदराबाद और नई दिल्ली से प्रकाशित | website : <https://www.shubhlabbhdaily.com> | संपादक : गोपाल अग्रवाल | पृष्ठ : 14 | मूल्य-8 रु. | वर्ष-7 | अंक-345



महेश बैंक

निदेशक मण्डल चुनाव

में प्रचण्ड बहुमत से
'संस्थापक पैनल'
से विजयी निदेशकों को

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ

जीत उसी की जो रहे सत्य के संग

काँप उठे छल, भयभीत हुआ पाखंड, जब सत्य ने स्वर उठाया,
टूट गए झूठ के सारे भ्रम, न्याय का सूरज मुस्कया।

सत्य की लौ जली अंधियारे में, झूठ स्वयं ही हार गया,
क्षणिक था असत्य का अहंकार, सत्य सदा ही अमर रहा।



श्री अमित लड्डा (गग्गु)



श्री दीपक कुमार बंग



श्री देवेन्द्र झंवर



श्री गोविन्द नारायण राठी



श्री कैलाश मंत्री



श्री मनोज लोया



श्री मुकुन्दलाल बाहेती



CA मुरली मनोहर पलोड़



श्री पवन कुमार लोहिया



श्री रुपेश सोनी



आपके कुशल
नेतृत्व में बैंक का
सर्वांगीण विकास हो
इन्हीं शुभकामनाओं
के साथ



श्री विनोद कुमार बंग



CA अल्का झंवर



श्रीमती कविता तोष्णीवाल

शुभकामनाओं सहित - श्रीगोपाल बंग, हरिकिशन बंग, श्रीकिशन बंग, राधेश्याम बंग
घनश्यामदास, नवलकिशोर, दिनेश, राजेश, रुपेश, निलेश, अल्पेश, सुमेश, श्रीकान्त, राज,
रामदेव, अक्षय, राघव, केशव, माधव, आरव, अर्णव एवं समस्त बंग परिवार



मुरलीधर रामप्रसाद बंग

हैदराबाद

संपादकीय

पीड़ा से मुक्ति

[illegible]

सुप्रियम कोर्ट की स्पष्ट दिष्णणी थी कि हमें अब कुछ करना होगा, इस तरह के त्रासद जीवन की कोई तार्किकता नहीं है। दरअसल, यह मामला एक 32 वर्षीय सुप्रियम कोर्ट की, जो पिछले 13 साल से कोमा जैसी स्थिति में है। यह अब केवल महज चिकित्सीय त्रासदी का मामला नहीं रह गया है। अब यह एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रश्न भी बन चुका है। निश्चित रूप से यैचित् अदालत की दिष्णणी देश में जीवन के अंतिम क्षणों में गरिमापूर्ण व्यवहार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। निश्चित ही यह प्रसंग अतीत में बहुचर्चित अरुणा शानबाग के मामले की यादें फिर से ताजा कर देता है। इस प्रसंग ने ही देश को पहली बार निश्चिप्ट इच्छामृत्यु के प्रश्न का सामना करने के लिये बाध्य किया था। वर्ष 2011 में, सुप्रियम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के मामले में फैसला सुनाते हुए, सैद्धांतिक रूप से निश्चिप्ट इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी।

दरअसल, अरुणा शानबाग एक भयानक हमले के बाद से ही 42 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति में रहि रही थीं। भले ही अदालत ने इस मामले में निर्णयित इच्छामृत्यु की अनुमति दी, लेकिन साथ ही उसके साथ कुछ प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपायों के अनुपात में भी निर्देश दिए थे। निश्चित रूप से इस मामले में अदालत फैसला नैतिक प्रेरणा का सोत भी बना।

त्रासदी को स्थिति है। जहाँ परिवार एक ओर भावनात्मक संकट से जुझ रहे होते हैं, वहीं रोगी को उपचार से जितना आर्थिक बोझ भी निरंतर बढ़ता जाता है। दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर भी स्वाल उठते रहे हैं। निरसंहार, अलालत को जटिल पहलियाँपूर्ण मृत्यु में जैविक अस्तित्व के कठोर विस्तार के बजाय रोगी की मुक्ति और परिवार को पीड़ा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे में यदि एम्स 17 दिसंबर तक मामले में जीवन की निरन्धकता को पुष्टि करता हो, तो निरपेक्ष इच्छामृत्यु की स्वीकृति एक मिसाल कायम कर सकती है। इसके बाद दुष्प्रयोग के खिलाफ मजबूत उपग्रहों को भी स्पष्ट किया जा सकता। साथ ही जीवन के अंतिम विकल्पों का समान किया जा सकेगा। देश के नीति-निर्देशकों को जो काम जैसी अवस्था में सालों जुझते लोगों के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने चाहिए, जिससे ऐसे रोगियों की उपचारमार्ग देखभाल और पामश को एकीकृत किया जा सके। मानवीय करुणा की मांग है कि जीवन की पवित्रता और पीड़ा को रूढ़ता के बीच मतुलन बनाया जाए। इच्छामृत्यु पर समर्पत से होगी तो मानवता को कायम क्रूता जा सकत है। न्यायपालिका को ऐसा न्याय देना चाहिए, जो रोगी को पीड़ा से मुक्त करे और एक करुणमृत्यु पालिका का मार्ग प्रशस्त करे।

કુદર

अलग

प्रेम-विवाह पर राजी

बदलते

बदलते वक्त की धारा में युवाओं में बढ़ते प्रेम विवाह के रूझान को देखते हुए अब तक करदर रही छापाओं ने भी रुख बदला है। जैसे कह रहे हैं कि यदि मां-बाप रोज तो क्या करेगा पापाजी। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री नरगज के गाँव सोरम में देशभर की छापा पंचायतें तीन दिन तक जुटीं। जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखण्ड, छत्तीस, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान आदि की विभिन्न जाति-धर्मों की 36 खास विचारदरियों के प्रतिनिधि जुटे। रोचक यह है कि एक लाख से अधिक भागीदारों में आधे करीब 20-35 वर्ष के युवा थे। वजह यह भी थी कि छापाओं की सख्तों से बड़ी संख्या में युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है। हालांकि, इस पंचायत में मौजूदा सामाजिक कुतूहिलों मसलन इज्जत के नाम पर होने वाली हत्याएँ, दर्दज, भ्रूण-हत्या, मृत्यु-भोज जैसे चरित्रों पर व्यापक विचार हुआ, लेकिन प्रेम विवाह को मुद्दा मुखरता से छाया रहा। महत्वपूर्ण बात यह रही कि सर्वखापा ने तय किया कि यदि माता-पिता की सहमति से प्रेम विवाह होता है तो खापा हस्तक्षेप नहीं करेगा। सर्वखापा पंचायत में देश की सबसे बड़ी बालियान खाप के प्रश्नाने ठिकेत का कहना था कि यहां इतने ज्यादा लोग इसलिए जुटे हैं कि मुझे कहीं राजनीतिक या किसानों के न होकर, प्रेम-विवाह, अंतरजातीय विवाह शुरू करने, दर्दज न लेने, मृत्युभोज बंद करने जैसे ज्वलंत विषयों से जुड़े हों। आम राय रही है कि जिस विवाह को लेकर मां-बाप की सहमति होगी, उसमें समाज, रिस्तेदार अथवा खापा हस्तक्षेप नहीं करेगी। दरअसल, खापा के रवैये में लचीलापन आमों को एक बड़ी वजह यह रही है कि युवा तेजी से प्रेम विवाह की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। लेकिन जहां ऐसा करने में सख्ताई है वहां बड़ी संख्या में युवा कुंआरे बने हुए हैं।

दृष्टि

कोण

ट्रांसजेंडर की पहचान और अधिकार: समानता की राह में जरूरी सवाल

भारतीय

समाज विविधताओं से भरा हुआ है लेकिन इस विविधता के बीच कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जिन्हें लंबे समय से उपेक्षा, भेदभाव और सामाजिक वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा है। ट्रांसजेंडर समुदाय उन्हीं में से एक है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट और संसदीय ने इस समुदाय को समान गरिमा और अधिकार दिए हैं, फिर भी व्यावहारिक जीवन में इस अधिकारों के क्रियान्वयन में कई बाधाएं नजर आती हैं। हाल ही में राजस्थान में रोडवेज बस टिकट श्रेणी को लेकर उठा एक विवाद इसी विफलता का और संकेत करता है। 11 दिसंबर को जयपुर से जोधपुर जा रही राजस्थान रोडवेज बस में यात्रा कर रही ट्रांसजेंडर कली राजेशा सिंह को टिकट बनवाते समय यह महसूस हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन में केवल दो विकल्प 'पुरुष' और 'महिला' उपलब्ध हैं। उनकी पहचान इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए उन्होंने आपत्ति जताई। उनका सामना सीधा था—'जब मेरी अपनी लैंगिक पहचान है, तो टिकट भी

मुझे क्यों महिला या पुरुष के रूप में देना पड़ेगा?' ट्रांसजेंडर को जवाब सिस-मशीन में। कंडक्टर का जवाब सिस-मशीन में। वैसे विकल्प है, वैसे सकता है। लेकिन यह प्रशासनिक वास्तविकता को नहीं समझता समुदाय वर्षों से अपनी पहचान, अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। एक शोधकर्ता नहीं थी लैंगिक सरकारी व्यवस्थाओं में मौजूद उजागर करने के जो लैंगिक विविधताओं में पीछे हैं। बस टिकट सुविधा में भी यह 'पुरुष' और 'महिला' कोई विकल्प नहीं मिलता, तो स्वाभाविक है कि ट्रांसजेंडर को यह है? सरकारी फॉर्म, पहचान पत्र, नौकरी आवेदन—कठिनाई आज लिंग के जगह मौजूद नहीं है।

मुझे क्यों महिला या पुरुष के रूप में चिन्हित किया जाए ?” ट्रांसजेंडर के लिए कोई अलग विकल्प मशीन में नहीं था। कंडक्टर का जवाब सस्पन्स आधारित था— मशीन में जैसा विकल्प है, वैसा ही टिकट दिया जा सकता है। लेकिन यह प्रशासनिक तर्क उत समाजिक वास्तविकता को नहीं समझता जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय वर्षों से अपनी पहचान, सम्मान और समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। यह विवाद केवल एक क्षणिक घटना नहीं था बल्कि यह हमारे समाज और सरकार की व्यवस्थाओं में मौजूद उन गहरी खामियों को उजागर करता है जो लैंगिक विविधता को अब भी स्वीकार करने में पीछे हैं। बस टिकट जैसी बुनियादी सुविधा को भी यहाँ “पुरुष” और “महिला” के अलावा कोई विकल्प नहीं मिलता, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ट्रांसजेंडर की पहचान का सम्मान कहाँ है ? सरकारों—पहचान पत्र, अस्पताल रजिस्ट्रार, नौकरी आवेदन—कई स्थान आज भी ऐसे हैं जहाँ तीसरे लिंग के लिए जगह मौजूद नहीं है। इस मामले ने यह भी

सुनील कुमार महला

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सिडनी में बोंबी बीच (समुद्र तट) पर हमलावरों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की घटना में ड्रगबारी वाली नागरिक सप्ताह 16 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार घायलों में एक बच्चा और दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने इससे आगेकी हमला करार दिया। फ्लिन्टीन बड़ी बात है कि बोंबी बीच में अंदर पर्व के पास, जो कि भीड़-भाड़ वाली जगह है। (ऑस्ट्रेलियाई ईस्टर्न डेली टेलीग्राफ टाइम के मुताबिक शाम को करीब 6.47 पर) दो लोगों की ओर से सार्वजनिक जगह पर गोलीबारी की गई और इलाके को दहला दिया गया। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में हनुकुका त्योहार मना रहे यहूदियों पर यह आतंकी हमला हुआ है, जो बुद्धि की शर्मनाक और निन्दनीय है। हालांकि, पुलिस की गोलीबारी में एक हमलावर भी मारा गया है तथा दूसरा घायल बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुई यह आतंकी घटना साफ संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया भी कहीं न कहीं अन्य देशों की भांति आतंकवाद का शिकार है।

देश

दुनिया से

शिक्षा सुधार : व्यवस्था बदले बिना नहीं बनेगा विकसित भारत

भारतीय

वास्तविक वृद्धि हेतु आवश्यक है कि पुरानी बाधाओं को हटाकर नए अवसरों का प्रयोग किया जा सके। यह हो चुके संस्थागत ढांचों एवं अप्रासंगिक नियमों के माध्यम से समाधान किया जाए। शिक्षा सुधारों के तहत वास्तविक रूप में बनेगी विकासभरी भारत जब तक कि 'विकास नहीं' बरने के संकेतक के साथ अ रहा है, तब यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था इस लक्ष्य की मजबूती नहीं पा रही। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक समर्थता उसकी सामग्रीकरण, ज्ञानसृजन और नवाचार क्षमता में होती है। इस दृष्टि से प्रस्तावित विकासभरी भारतीय अधीक्षण विधेयक भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था (आइ) २०२० ने शिक्षा सुधार को दिशा स्पष्ट कर दी है। नई संस्थागत व्यवस्था, बहु-विषयक शिक्षा, आधारित सोख और 'लाइट डट टाइड रेगुलेशन' आधाराकार को बढ़ में खा। लेकिन पिछले वर्षों के यह भी बताता है कि केवल नीतिगत घोषणाओं से वह नहीं बदलती। जब तक नीति को लागू करने के लिए बाध्यकारी और सक्षम वैधानिक ढांचा न हो, तब तक फलदायी और सम्मेलनों से आगे नहीं बढ़ पाते। विषयगत शिक्षा अधीक्षण विधेयक इसी नीति-का अनुत बन को पाठने का प्रयास है। आज उच्च शिक्षा का निष्पादन कई संस्थाओं या यूनीसर्स, एआईसीटीई, एनसीटीई के बीच बंटा हुआ है। समय के साथ यह बहु-निष्ठा व्यवस्था जटिल, धीमी और बोझिल बन गई। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पाठशाला, नगर का विकास आकाशिक नवाचार हेतु अनेक सत्रों पर स्वीकृत पड़ती है। परिणामस्वरूप संस्थान गुणवत्ता सुधार वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तैयारी के बजाय अनपुलक कार्य और औपचारिकताओं में बालू रहते हैं। यही कारण कि प्रतिभासंपन्न होने के बावजूद भारतीय उद्योग अपेक्षा वैश्विक स्थान हासिल नहीं कर पाई है। प्रभावित विधेयक का मुख्य उद्देश्य इसी संरचनात्मक समस्या को दूर करना है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए एक अधीक्षण अधिकरण की परिकल्पना की गई है।

मौजूदा नियामक संस्थाओं का समन्वयपूर्ण होगा।



नियमन, मानक रूपांतर, मान्यता एवं विनियमण जैसे कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि हितों के टकराव से बचा जा सके। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के इस प्रकार की भूमिका-विभाजन अत्यधिक बताते हैं कि इस प्रकार की भूमिका-विभाजन व्यवस्था से शासन अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनता है। इस विधेयक का महत्व केवल प्रशासनिक सरलीकरण तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक ताला उच्च शिक्षा संस्थानों को मिलने वाले स्वायत्तता में निहित है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय-आधार पर अधिक स्वतंत्रता मिलेगी वे अपने पाठ्यक्रम-स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था, उद्योग जात की मांग और वैश्विक मानकों के अनुरूप गढ़ संवेगों। बहु-विषयक शिक्षा, उद्योग-अकादमिक सहयोग और शोध आधारित शिक्षण को इससे वास्तविक गति मिल सकती है। दीर्घकाल में सरकार का यह कदम भारत में विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालयों और समाजोपयोगी शोध पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रख सकता है। अतः इस विधेयक का नीति-दृष्टि और संस्थागत व्यस्तता को बनाए रखेगा, नतीजा - दुष्टाचारों को नष्ट कर देगा। अतः इस विधेयक को लेकर कुछ अपशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपशंका यह है कि भारत में वैश्विक ज्ञान और नवाचार वेद बनने की दिशा में बाधाएं होंगी, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए पर्याप्त होंगी। फिर भी, इस विधेयक को लेकर कुछ अपशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपशंका यह है कि भारत में वैश्विक ज्ञान और नवाचार वेद बनने की दिशा में बाधाएं होंगी, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए पर्याप्त होंगी।

अक्सर

देखा गया है कि आतंकी समाज के बीच ही छिपकर रहते हैं। इसलिए और जागरूक को चप्चे-चप्चे पर अपनी पीजी नजर रखनी होगी, सर्वत और जगह का रहरा होगा। सच तो यह है कि आतंकवाद के निमित्त बढ़ते स्वरूप से निम्नलिखित हो गए हैं प्रभावों तरीकों को समय रहते अपनाना होगा। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सिडनी में घंटों बीच (स्मृत) पर हमला करने में अंतर्धुंध गोलियोंवाली बंदी ने इज़रायली नागरिक समेत 16 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 29 लोग घायल बनाए जा रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार घायलों में एक बच्चा और दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। हालाँकि बड़ी बात है कि बॉडी चीच में आंच पाये पास, जो की भेड़-डाल जाने वाला 6.47 फीट (ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न डैवडाइ टाइम के मुताबिक) म को क़रीब 6.47 फीट) दो लोगों की ओर से सर्वजनिक जगह पर हमला लोलीवाली को गई और इलाके को दहला दिया गया । बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में हनुक्का त्यौहार मना रहे यहीदियों पर यह आतंकी हमला हुआ है, जो बहुत ही शर्मनाक और निर्दयी है। हालाँकि, पुलिस को यह पता चल चुका है कि लोलीवाली को एक हमलावर भी मारा गया है तथा दूसरा घायल बनाया जा रहा है, जिसे गिरफ़्तारी भी कर लिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुई यह पहली आतंकी घटना प्राप्त संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया में कहीं न कहीं अन्य देशों की भाँति आतंकीकरण का शक्तिार है। पाठकों को बताता चूंकि एक हमलावर को पकड़ा जाना पिछले साल मूल के 2.4 घण्टा वस्तु अनुक्रम के रूप में हुई है तथा दुनियाभर के नेताओं ने इस आतंकी हमले की घोषणा की है। स्वयं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अब्नेन्जो ने वैसावा प्रकारों से कहा कि वह इस तरह सारहात से बेहद दुःखी हैं उन्होंने कहा, "हनुक्का के पहल दिन यहाँ ऑस्ट्रेलियाई लोगों को निशाना बनाना, हमला करना या हमला है कि यह यहीदियों और आतंकी वृत्त है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के दिल पर हमला किया है। प्रधानमंत्री नेन्द्र मोदी ने हमले निदा करते हुए प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदन व्यक्त किया है तथा साथ ही यह बात भी ध्यात में रखते हैं कि भारत के प्रति शुद्ध सहयोग रखता है। और इसके सभी रूप व अभिव्यक्तियों के विरुद्ध डाई का समर्थन करता है। इंप्र, इज़रायल के प्रधानमंत्री बेजागिन ने कहा है यह बात है कि यह लोलीवाली बुनियाजित जहा है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को चेतावनी दी थी कि उनके देश की नीतियाँ विश्ववैधविधि को बढ़ावा देती हैं। यहीदियों थाचना तब पैवती है जब तक कि तुम चूप रहते हैं। आपको कमजोर दिखाने की जगह कार्रवाई करोनी चाहिए। बहरहाल, गोरेलवत है कि ऑस्ट्रेलिया की लापरवा 2.8 करोड़ ऑस्ट्रेलिया में करीब 1.17 लाख यहीद रहे हैं। सात अक्टूबर 2023 को सप्तमा द्वारा इज़रायल पर किए गए हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहीदों की घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं। संसार की विशेष दूत जिलियन सेहल

के अनुसार, इन घटनाओं की संख्या तीन गुना से भी ज्यादा हो गई है, जिन्होंने हमले, तांफोइड, धर्मघरों और लोगों को डराने की घटनाएँ शामिल हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिछली गीमियों में सिडनी और मैनचेस्टर जैसे बड़े शहरों में हथु यहुदी विरोधी हमलों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की लगभग 85 प्रतिशत यहुदी आबादी इन्हीं शहरों में रहती है। प्रथममंत्री एथार्थ अब्बन्जी ने अगस्त में ऐसे दो हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था और उसके साथ राजनयिक संबंध भी तोड़ दिए थे। वहीं, ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं आम नहीं हैं। 1996 में तस्मानिया के पोर्ट आर्थर में हुई भयावह गोलीबारी के बाद, जिसमें 35 लोग मारे गए थे, सरकार ने हाथियार कानून (नगल) को बेहद सख्त बना दिया था। इसके बाद से आम लोगों के जानवरों हलाल करना बहुत कठिन हो गया। इस सिल में गोलीबारी की गिनी-चुनी बड़ी घटनाओं में 2014 और 2018 के वुड हत्या-आत्महत्या के मामले और 2022 में क्वींसलैंड में हुई एक गोलीबारी शामिल हैं। वृत्त मालिका, देश में हिंसा की घटनाएं कम हैं, लेकिन हाल के वर्षों में यहुदी विरोधी हमलों ने गंभीर ज़िदा पैदा की है। बहरहाल, यहां यह कहना जरूरी नहीं होगा कि आज के दौर में यह साफ दिखाई दे रहा है कि आतंकवादी अब भी ड्राइव वाले स्थानों को निशाना बनाकर दशरत पैसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक जानमाल का नुक़सान कर सके औरतलबत है कि विश्व में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित (शिकार) देशों में आज ब्रज़ील, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, नाइजीरिया, सोमालिया, भारत, यमन, माली तथा फिलिस्तीन-इज़राइल क्षेत्र शामिल हैं। आतंकवादी दशकों से तालिबान, आईएस जैसे संगठनों की हिसा का वेद रहा है। वहीं पर पाकिस्तान आतंकी संघटनों, अफ़ग़ानी हलालों और सीमा-पार आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है। इराक आईएस के उदय के बाद भी आतंकी हिसा झेल चुका तथा गृहयुद्ध के साथ आतंकवादी का उत्तरपूजा इलाकों जहां बोको हराम जैसे आतंकी संगठन से बुरी तरह से प्रभावित है, वहीं पर हमारा देश भारत सीमा-पार

आप का

मज्जरिमा

तिरुवनंतपुरम की जाति और टूटता राजनीतिक मिथक

केरल

केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों को केवल एक राज्य-विशेष केंद्र राजनीति की घटना मानना एक गंभीर भूल होगा। हितवन्तनपुर नगर निगम में 45 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की जीत और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की आंशिकतः सशक्त प्रदर्शन दूर अलग दूर राष्ट्रीय राजनीति की प्रतियोगिता का विस्तार है, जो बीजेपी एक दशक से भारतीय लोकतंत्र को नए सिरे से गढ़ रही है। ये नतीजे न सिर्फ 2026 के केरल विधानसभा चुनावों को भूमिका हैं, बल्कि 2029 के आम चुनावों को आहट भी अपने भीतर समेटे हुए हैं।

केरल परिदृश्य में देखें तो बीजेपी का केरल में उभार एक रणनीतिक प्रहरी है। अब कट दक्षिण भारत, विशेषकर केरल, बीजेपी की लिए एक कठिन भूगोल रहा है। मजबूत वामपंथी परंपरा, सामाजिक सुधार आंदोलनों के विरासत और सिंगले चेतना ने केरल का राष्ट्रीय दक्षिणपंथी राजनीति से काफी हद तक अलग रखा। ऐसे में हितवन्तनपुर जैसी राजधानी में जीत बीजेपी के लिए केवल एक सीट नहीं, बल्कि एक मनावैज्ञानिक बदल है। यह संदेश दिल्ली से लेकर नागपुर तक स्पष्ट है, कि बीजेपी अब “अजेय किले” माने जाने वाले राज्यों में भी धीरे-धीरे सशक्त लगाने की स्थिति में है।

स्थाना ही नहीं यह परिघटना उस राष्ट्रीय रणनीति से भी मेल खाती है, जिसमें बीजेपी राज्यों का विकास और शहरी संस्थाओं को स्थानीयक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब दक्षिण में भी पार्टी शहरी मध्यवर्ग, यूपी पेशेवरों और आर्कांक्षी मतदाताओं को लक्षित कर रही है। केरल में यह रणनीति खास तौर पर "सुशासन", "भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन" और "विकास बनाम वैचारिक जुड़ना" जैसे मॉडल के जरिये आगे बढ़ती दिखती है। वहाँ कांग्रेस के लिए अकेल के ये नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर दोहरी चरमपंक्त खोते हैं। एक ओर, यह पार्टी के लिए राहत का संकेत है कि वह अभी भी कुछ राज्यों में बीजेपी-विरोधी राजनीति का केंद्र बना सकती है। दूसरी ओर, यह चेतावनी है कि यदि कांग्रेस अपनी वैचारिक स्पष्टता और संघटनात्मक ऊर्जा को पुनर्व्यापित नहीं करती, तो उसका स्थान बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच सिमटना जाएगा। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस आज जिस अस्थिरता से जूझ रही है, केरल के स्थानीय चुनाव उसके छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उतार की तरह सामने आते हैं कि जीत संभव है, पर शतें बदल चुकी हैं।

वामपंथ के लिए यह पराजय सिर्फ राज्य सरकार के खिलाफ असंतोष नहीं, बल्कि राष्ट्रीय वाम रणनीति के क्षरण का प्रतीक भी है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बाद केरल ही वह प्रमुख राज्य बचा है, जहाँ वामपंथ सत्ता में है। स्थानीय चुनावों में आई गिरावट यह संवाल खड़ा करती है कि आखिर इस राष्ट्रीय वाम प्रांशिक

राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो बीजेपी का केरल में उभार एक रणनीतिक प्रतीक है। अब तक दक्षिण भारत, विशेषकर केरल बीजेपी के लिए एक कठिन भूगोल रहा है। मजबूत वामपंथी परंपरा, सामाजिक सुधार आंदोलनों की विरासत और संघीय घेताना केरल को राष्ट्रीय दक्षिणपंथी राजनीति से काफ़ी हद तक अलग रहा। ऐसे में तिरुवनंतपुरम जैसे राजधानी में जीत बीजेपी के लिए केवल एक सीट नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बदल है। यह संदेश दिल्ली से लेकर नागपुर तक स्पष्ट है, कि बीजेपी अब "अजेय किले" माने जाने वाले राज्यों में भी धीरे-धीरे सेंध लगाने की स्थिति में है। इतना ही नहीं यह परिघटना उस राष्ट्रीय रणनीति से भी मेल खाती है, जिसमें बीजेपी स्थानीय निकायों और शहरी संस्थाओं को राजनीतिक

प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब दक्षिण में भी पार्टी शहरी मध्यवर्ग, यूपी पेशेवरों और आर्कांक्षी मतदाताओं को लक्षित कर रही है।

सामाजिक आधार मजदूर, किसान, निम्न-मध्य वर्ग से धीरे-धीरे दूर होती जा रही है ? राष्ट्रीय स्तर पर वैचारिक पहलू ही हाशिये पर हैं, और केरल में कमजोर होना संकेत उत्पन्न किए एक गहरी वैचारिक चुनौती है। सामाजिक दृष्टि से भी केरल के नतीजे राष्ट्रीय बहस को प्रभावित कर रहे हैं। लंबे समय तक केरल को “राजनीतिक परिपक्वता” और “सांसाध्यिक शौद्धी” का मॉडल माना गया। लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ भी पहचान, धर्म और सांस्कृतिक राजनीति के प्रश्न उत्पन्न लगे हैं। बीजेपी की शहरी सफलता और काँग्रेस-धारा की प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि केरल अब पूरी तरह उत्पन्न राष्ट्रीय राजनीतिक धारा से अछूता नहीं रहा, जहाँ भावनात्मक मुद्दे, प्रतीकात्मक राजनीति और सोशल मीडिया के जरिये जनमत निर्माण निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इन चुनावों का एक अहम राष्ट्रीय संकेत यह भी है कि स्थानीय चुनाव अब “छोटे चुनाव” नहीं रहे। जिस तरह दिल्ली, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थानीय चुनाव और विधानसभा चुनावों को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देखा गया, उसी तरह केरल के नतीजे भी केंद्र को राजनीति पर असर डालते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बने नए राजनीतिक संतुलन में बीजेपी, काँग्रेस और क्षेत्रीय शक्तियाँ तीनों के अंतर्गत केरल एक रणनीतिक प्रयोगशाला बन सकता है। 2026 का केरल विधानसभा चुनाव इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यह तय करेगा कि क्या बीजेपी दक्षिण में एक स्थायी शक्ति के रूप में स्थापित हो पाएगी, क्या काँग्रेस राष्ट्रीय विकास के रूप में अपनी विवशनीयता लौटाएगी, और क्या वामपंथ अपने वैचारिक और संगठनात्मक संकट से उबर पाएगा।

आतंकवाद, कश्मीर और बड़े शहरों में दहशत आतंकी हमलों से प्रभावित है। गृहयुद्ध और आतंकी गुटों की मौजूदगी के कारण यमन में भारी संकट उत्पन्न हो रहा है। मालदीव आतंकी संगठनों के कारण) हिसा का शिकार है। फिलिस्तीन/ इराक/इराक क्षेत्र तो लंबे समय से संघर्ष और आतंकी हमलों का सामना कर रहा है और यह बात किसी व्यक्ति विशेष से छिपी हुई नहीं है। सच तो यह है कि आतंकी की समस्या आज केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश इसकी चपेट में हैं। हालत या ममाला ऑस्ट्रेलिया का है, जहाँ सिडनी में यहुदी समुदाय पर हमला किया गया हमला पूरे देश को झकझोर देने वाला साबित हुआ है। आतंकीयों ने सड़क के बाँदी बीना पर आर्गो जित हनुक्का पर्यटन उल्लेख के दौरान सचनक गोलियों पर कर दी, निरुध्द लोग मार गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वास्तव में यहुदी समुदायों ने यह शांति भंग करने व आतंक पैलाने के उद्देश्य से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पिछले कुछ समय में यह देखा जा रहा है कि आज कई जगहों पर युवा और आतंकवाद का कट्टर विचार धाराओं की ओर लगातार आकर्षित हो रहे हैं, खासकर अफगानिस्तान युद्ध इस्तेमाल के ज़रिये। वास्तव में यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हालाँकि इससे निपटने के लिए दुनिया भर के सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, सरकारें व सेनाएं भी लगातार सर्वेच हो रही हैं। गौरतलब है कि एक संयुक्त चेतावनी में आतंकी, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूज़ीलैंड जैसी फाइव आइयू सुरक्षा एजेंसियों ने यह बात कही है कि युवा रिक्रूटमेंट फ़ैशन (कट्टर विचारों के प्रभावित होने) की संख्या बढ़ रही है। इससे जुड़ने वालों में लगभग 20 प्रतिशत प्राथमिक आतंकवाद के मामलों में युवा शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई संघीय प्रस्थित (एएफपी) ने भी यह बात कही है कि बहुत छोटे बच्चे भी ऑनलाइन उपग्रहीत समग्रि तब पहुँच रहे हैं। जिनमें से कई 17 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। दिल्ली धमका की जांने ने आतंक के इसी नए पैटर्न को उजागर किया है, जिसमें उच्चशिक्षित पेशेवरों की संयंत्रिता समेत आई है। इसी कारण सुरक्षाबलों के समेत नए 'व्हाइटट्री लॉ टेरर इकोसिस्टम' को तोड़ना सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता बन गया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की भीभूषक कारणी अमर और महत्वपूर्ण है। वास्तव में आम आदमी को आम सतर्क रहना होगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधों की सूचना तुरंत नदीकी पुलिस थाने को देनी होगी। अक्सर देखा गया है कि अंतर्दी समान के बीच ही छिपकर रहते हैं। इसलिए आम आदमी को चर्चे-चर्चे पर अपनने पैनी नजर रखनी होगी, सतर्क और जागरूक रहना होगा। सच तो यह है कि आतंकवाद के निरंतर बदलते स्वरूप से निपटने के लिए नए और प्रभावी तरीकों को समर्थन देना अपनाना होगा। इसके मूल कारणां को समझकर उद्दे छहम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।

के ऐतिहासिक नालसा निर्णय ने ट्रांसजेंडर को स्वतंत्र तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और कहा कि "लैंगिक पहचान व्यक्ति की आत्म-पहचान का मूल आधार है। इसे समाज देना राज्य का अधिवाचनकृत्य है।" इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि किसी व्यक्ति का लिंग उसके जन्म प्रमाण या सामाजिक अपेक्षाओं से सदा नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक पहचान से निर्धारित होता है। इसके बाद भारत सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम: ट्रांसजेंडर की स्व-पहचान को मान्यता देता है, भेदभाव पर कानूनी प्रतिक्रिया देता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने का आदेश देता है, सरकारी सेवाओं में समावेशी नीतियों को मांग करता है लेकिन वास्तविकता यह है कि— सरकारी फॉर्म, वस-ट्रेन टिकट, शौचालय, स्कूल रजिस्टर, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, नौकरों के आवेदन अद्वितीय जगह अभी भी "पुरुष" और "महिला" से आगे नहीं बढ़ पाते।



महेश बैंक के चुनाव में ऐतिहासिक जीत का बुधवार को द्रोपदी गार्डन में जश्न मनाते हुए संस्थापक पैनल के विजयी उम्मीदवार। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद अंजनी कुमार यादव, विधायक मिट्टू गोपाल, बेगम बाजार पार्श्व जी. शंकर यादव सहित संस्थापक पैनल के शुभचिंतक हजारों की संख्या में उपस्थित थे। लोगों ने शॉल व हार पहनाकर सभी विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर वरंगल, निजामाबाद व अन्य क्षेत्रों के समर्थक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कोंडागट्ट हनुमान मंदिर को वन विभाग के नोटिस से भावनाएँ आहत : रामचंद्र राव

हैदराबाद, 17 दिसंबर (शुभ लाभ व्यूरो)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने कोंडागट्ट हनुमान मंदिर को वन विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि हजारों वर्ष पुराने मंदिर से हिन्दुओं की भावनाएँ जुड़ी हैं। ऐसे में मंदिर को नोटिस दिया जाना भक्तों की आस्था पर हमला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने कहा कि वन विभाग द्वारा

नोटिस में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के 3ए, 3बी सेक्शन के अंतर्गत 15 दिनों के भीतर विवरण देने, वरना कानूनी कदम उठाने की चेतावनी दी गई है, जिससे भक्तों में चिंता है। उन्होंने कहा कि वन विभाग जिस 6 एकड़ भूमि पर क्लेम कर रहा है उस पर अन्नदान सत्रम, वॉटर प्लांट आगम पाठशाला, वेद विद्या हॉस्टल, भोजन शाला, पार्किंग आदि संचालित हैं तथा रोजाना वाहन पूजा की जाती

है। इसके अलावा गिरि प्रदक्षिणा भी की जाती है। उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत ही हस्तक्षेप कर भक्तों के विश्वास व धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए समस्या का शास्वत परिष्कार निकालने की मांग की। रामचंद्र राव ने आगे कहा कि सरकार को चाहिए कि रेवेन्यू असिस्टेंट सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स, धर्मस्थ विभाग व वन विभाग द्वारा भूमि की सीमाएं व परिधि नोटिफाई कराये।

रामचंद्र राव ने चिंता जताते हुए कहा कि विवाद का समाधान निकालने की जिम्मेदारी सरकार की है, परंतु वह अंजान बनी बैठी है। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने निर्माण के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट-1980 के 2ए नियम के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन विभाग की अनुमति अनिवार्य है बताते हुए मंदिर को नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि कोंडागट्ट मंदिर के पास स्थित 6 एकड़ भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि के तौर पर रामसागर स्थित देवालय की भूमि में से 8 एकड़ भूमि देने की पेशकश धर्मस्थ विभाग ने की है।

जीएचएमसी चुनाव जब भी

हों, मेयर भाजपा का बनेगा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) चुनाव जब भी होंगे, भाजपा की जीत तय है और मेयर भाजपा का ही बनेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, उससे साबित हो रहा है कि जनता भाजपा की ओर विश्वास की नजर से देख रही है। उन्होंने आउटर रिंग रोड (ओआरआर) के भीतर की 27 म्युनिसिपालिटियों व निगमों का जीएचएमसी में विलय करके 150 वार्डों की संख्या 300 किए जाने के पीछे सरकार का राजनीतिक हित बताया। रामचंद्र राव ने कहा कि विलय का निर्णय कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक हितों तथा मित्रदल मजलिस पार्टी को खुश करने के उद्देश्य से लिया गया है जिसका भाजपा कड़ा विरोध करती है। उन्होंने सरकार के जनविरोधी निर्णय के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिन म्युनिसिपालिटियों का विलय किया गया है, उन पर टैक्स का भार बढ़ेगा। पहले से ही कई म्युनिसिपालिटियों में मौलिक सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण जनता परेशान है। कई क्षेत्र विकास से अछूते हैं। पियजलापूर्ति व ड्रेनेज समस्या जस की तस बनी हुई है। जरा सी बारिश होने पर कई बस्तियां, कॉलोनियां जलभराव की समस्या से दो चार होने लगती हैं।

आज का अल्पाहार

राधे राधे ग्रुप

प्रेमा बाई पिट्टी
(धर्म पत्नी स्व. श्री दामोदर दाल पिट्टी)
के तृतीय पुनिया तिथि के अवसर पर

वितरण स्थल : मेट्रो पिक्चर नं. A-1265, पब्लिक गार्डन रोड

SATISH KUMAR GUPTA 92465 05234
JAGAT NARAYAN AGARWAL 92465 35311
RAM PRAKASH GOEL 93910 14283
MAHESH AGARWAL 98490 98502

आज का अल्पाहार

राधे राधे ग्रुप

हर्षाली गुप्ता
के मासिक पुण्यतिथि के अवसर पर
विष्णु एजेंसीज सुलतान बाजार

वितरण स्थल : इंडो अमीकन कैंस हॉस्पिटल के सामने, के.वी.आर गार्डन के पास

SATISH KUMAR GUPTA 92465 05234
JAGAT NARAYAN AGARWAL 92465 35311
RAM PRAKASH GOEL 93910 14283
MAHESH AGARWAL 98490 98502

The Hyderabad Wholesale Art Silk Cloth Merchants Association
21-1-404, Art Silk Bhawan, Near Gupta Hospital, Rikab Gunj, Hyderabad-500 002 (Telangana)

ELECTION NOTIFICATION

Election notification is hereby issued for the elections of The Hyderabad Wholesale Art Silk Cloth Merchants Association for the year 2026-28 on Sunday, 4th January 2026 at VEG VYANJAN, Himayatnagar, Hyderabad.

Nominations are hereby invited for the following posts :
PRESIDENT, VICE PRESIDENT, HON. SECRETARY, JOINT SECRETARY, TREASURER AND 11 MEMBERS OF EXECUTIVE COMMITTEE

Office of The Hyderabad Wholesale Art Silk cloth merchants Association will function as preliminary office of election process.

ELECTION SCHEDULE

- 1) Issue of nomination forms on Wednesday 24th December 2025 from 1 PM to 3 PM
- 2) Submission of nomination forms on Friday 26th December 2025 from 1 PM to 3 PM
- 3) Display of List of nomination forms after scrutiny on notice board on Friday at 5-30 PM on 26th December 2025.
- 4) Withdrawal of nomination forms on Monday 29th December from 1 PM to 2 PM
- 5) Final list of candidates after withdrawal will be displayed on notice board on 29th December 2025 at 4 PM
- 6) Elections will be held on Sunday 4th January 2026 from 12 PM to 2 PM at hotel veg vyanjan, Himayatnagar, Hyderabad
- 7) Results will be declared on same day after counting.

RULES AND REGULATIONS

- 1) Nomination Forms will be issued on non refundable payment of fees as under
 - a) ₹ 3,000/- for the post of President
 - b) ₹ 2,000/- for the post of vice President, Hon. Secretary, Jt. Secretary, Treasurer
 - c) ₹ 1,000/- for the post of member Executive committee
- 2) An amount of ₹ 2,000/- shall be deposited as Security deposit at the time of filing nomination form. If a candidate secured more than 25% votes of total valid votes their security deposit will be refunded. In case if a candidate fails to get 25% votes of the valid votes their security deposit will be forfeited
- 3) Elections will be held based on the list provided by Hon. Secretary of Association
- 4) Any type of election campaigning via newspaper is strictly prohibited. However Candidates can campaign through Whatsapp. Any use of abusive language or mud slinging by candidates or members is strictly prohibited.
- 5) No candidate shall be allowed to contest for more than one post
- 6) One person shall be entitled to cast one vote only irrespective of his representation in more than one firm. Producing ID card issued by Association or any id card such as Adhar, PAN, Driving licence, voter id, passport is compulsory
- 7) For the election of Executive committee members casting 11 votes is compulsory. Casting less or more than 11 votes results to invalid vote
- 8) If any candidate violates any rules during the election process The Election officer has full authority to cancel the nomination of the candidate.
- 9) The decision of the Election officer will be final and binding on all candidates and members

MUKUND LAL AGARWAL
Chief Election Officer

VINAY JAIN, SESH KUMAR GOEL, RAHUL AGARWAL
Election officers

Place : Hyderabad
Date : 17-12-2025